**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2465**
**15.12.2025 को उत्तर के लिए**

**एनएएफसीसी की स्थिति**

**2465. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिसंबर 2025 तक जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में सहायता हेतु एनएएफसीसी के विशिष्ट उद्देश्य और लक्षित क्षेत्र क्या हैं;
(ग) एनएएफसीसी के अंतर्गत किस-किस प्रकार की कितनी परियोजनाएं वित्तपोषित हैं तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा परियोजना निष्पादन एवं प्रभाव आकलन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ग) जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना वर्ष 2015 में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अनुकूलन कार्यकलापों की सहायता करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में की गई थी जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। एनएएफसीसी के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कृषि, बागवानी, कृषि-वानिकी, पर्यावरण से संबद्ध कार्यकलापों, जल, वानिकी, शहरी, तटीय और निचले इलाके वाले क्षेत्रों में प्रणाली, आपदा प्रबंधन, मानव स्वास्थ्य, समुद्री प्रणाली, पर्यटन, पर्यावास क्षेत्र और अन्य ग्रामीण आजीविका क्षेत्रों में एनएपीसीसी और एसएपीसीसी के तहत संबंधित मिशनों के साथ संरेखित ठोस अनुकूलन परियोजनाओं/कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना।

ii. जलवायु परिदृश्य को तैयार और अद्यतन करना, संवेदनशीलता का अनुमान और जलवायु प्रभाव आकलन

iii. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और परियोजना चक्र प्रबंधन तथा जानकारी आधारित नेटवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण करना

iv. जानकारी प्रबंधन के माध्यम से परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन से दृष्टिकोण/सीख को मुख्यधारा में लाना।

एनएएफसीसी के तहत 30 परियोजनाएं 25 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फैली हुई हैं, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों; पानी; पारि-प्रणाली और जैव विविधता; और वानिकी क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। दिनांक 23 नवंबर, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अनुशंसा के आधार पर एनएएफसीसी को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से गैर-योजना में परिवर्तित किया गया था।

(घ) अगस्त 2025 में किए गए तृतीय पक्ष के आकंलन के अनुसार पूर्ण एनएएफसीसी परियोजनाओं की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

i. सामुदायिक पहुंच और जागरूकता: जलवायु अनुकूलन, जल सुरक्षा और संधारणीय आजीविका पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक समर्थन कार्यकलाप आयोजित किए गए ।
ii. जलवायु-अनुकूलन कृषि: खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सूखे और लवण-सहिष्णु फसलों, एकीकृत खेती और संधारणीय जलीय कृषि को बढ़ावा दिया गया
iii. संवेदनशील समुदायों के लिए सहायता: कौशल निर्माण, संसाधन उपलब्धता और मूल्य वर्धित उत्पादन के माध्यम से आदिवासी, महिलाओं और अधिकारों से वंचित लोंगो संवर्धित आजीविका।
iv. जानकारी और डेटा प्रणाली: जीआईएस मैपिंग, खुले डेटा प्लेटफॉर्म और राज्य जलवायु योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से जलवायु सूचना पहुंच को मजबूत किया।
v. अनुकूलन के लिए क्षमता निर्माण:, अनुकूलन कौशल, बाजार लिंकेज और सामुदायिक स्थिरता में सुधार करके कार्यान्वयन एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया

******